*सम्माननीय एस. एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश और आई. एस. तिवाना, न्यायाधीश के समक्ष।*

*गोपाल दत्त,–याचिकाकर्ता,*

*बनाम*

*हरियाणा राज्य–प्रतिवादी।*

*आपराधिक संशोधन संख्या 1294/1981।*

*27 जुलाई, 1982*

***खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम (XXXVII 1954) की धारा 11(3) और 16(1)(अ)–दूध का नमूना ठोस पदार्थों में कमी लेकिन वसा में नहीं–वसा की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक–आरोपी–क्या मिलावट का दोषी–नमूना भेजने में मामूली देरी–ऐसी देरी आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह के प्रमाण के बिना–क्या महत्वपूर्ण–धारा 11(3) के प्रावधान–क्या निर्देशात्मक।***

निर्णय: यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि निर्धारित मानक से विचलन के प्रतिशत के जोड़ या घटाव की प्रक्रिया का सहारा लेकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वस्तु मिलावटी नहीं है या निर्धारित मानक से मामूली विचलन को अनदेखा किया जा सकता है।

***(पैराग्राफ 4)***

जगत राम बनाम हरियाणा राज्य 1981, चंडीगढ़ कानूनी रिपोर्टर 684 (पंजाब और हरियाणा)।

हंस राज बनाम पंजाब राज्य, 1980(2) पी.एफ.ए. मामले 396।

(निरस्त किया गया।

अभिनिर्धारित किया है कि यह मानते हुए कि नमूना भेजने में अगले कार्य दिवस पर मामूली देरी हुई थी, ऐसी देरी आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह के प्रमाण के अभाव में महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 11(3) में नमूने के भेजने की समय सीमा का नियम केवल निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं। हालांकि, खाद्य निरीक्षक पर नमूने को बिना किसी देरी के लोक विश्लेषक को भेजने का कर्तव्य है।

***(पैराग्राफ 5)***

धारा 401 Cr. P. C. के तहत याचिका, श्री राम सरन भाटिया, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव के 12 नवंबर, 1981 के आदेश का संशोधन के लिए, जो श्री तरलोचन सिंह, J.M.I.C. पलवल के 23 सितंबर, 1980 के आदेश का आंशिक रूप से संशोधन करता है (गोपाल दत्त को खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 पढ़ी जा रही है धारा 16(1)(अ)(आई) के तहत दोषी ठहराया गया था, और उसे एक वर्ष की कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर, आरोपी-अपीलकर्ता को छह महीने के लिए और कठोर

कारावास भुगतना था) जिसे कठोर कारावास को छह महीने तक कम करने और जुर्माने को 2,000 रुपये तक कम करने के लिए संशोधित किया गया। जुर्माने का भुगतान न करने पर अपीलकर्ता को और छह महीने का कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।

**आरोप:**–खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के साथ पठित धारा 16(1)(अ)(आई) के तहत।

***अशोक कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।***

***जी. एल. बत्रा, वरिष्ठ डी.ए.जी., प्रतिवादी के लिए।***

***निर्णय***

***एस. एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश***

1. **जगत राम बनाम हरियाणा राज्य**[1] के मामले में निर्णय की प्रमाणिकता पर स्पष्ट संदेह के कारण, इस आपराधिक संशोधन की सुनवाई द्विविभाजित पीठ द्वारा आवश्यक थी।
2. चूंकि मुख्य मुद्दा यहाँ उक्त निर्णय की शुद्धता या अन्यथा है, इसलिए विस्तार से तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।गोपाल दत्त, याचिकाकर्ता, को खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम की धारा 1(डी) पढ़ी जा रही धारा 7 के तहत आरोपों पर पलवल के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, के सामने मुकदमे का सामना करना पड़ा, और दोषी पाए जाने के बाद एक वर्ष की कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अपील पर, गुरुग्राम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन सजा को छह महीने की कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने तक कम कर दिया। अपीलीय अदालत ने अपने फैसले में, जो इसकी विस्तृतता और स्पष्टता दोनों में उल्लेखनीय था, याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए छह तर्कों का विशेष रूप से उल्लेख किया और प्रत्येक पर विचार करते हुए उन्हें खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से मुख्यतः जगत राम के मामले (उपरोक्त) पर निर्भरता की गई थी, यह दबाव डालने के लिए कि लोक विश्लेषक द्वारा नमूने में पाई गई कमी केवल ठोस पदार्थों में और वसा की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने पर कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है। हालांकि, अपीलीय अदालत ने यह तर्क खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि **पंजाब राज्य बनाम तेजा सिंह**[2] की पूर्ण पीठ, अन्य उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट ने जगत राम के मामले से भिन्न दृष्टिकोण अपनाया था। जैसा कि पहले ही उल्लेखित है, जगत राम के मामले में विचार आवेदन चरण में ही संदेह में था और याचिका को द्विविभाजित पीठ द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकृत किया गया था।
3. हमारे समक्ष याचिकाकर्ता के लिए पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने जगत राम के मामले (उपरोक्त) में अपनाए गए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए जोरदार तरीके से बहस की। **हंस राज बनाम**

[1] 1981 Ch. Law Reporter 684 (Punjab and Haryana)
[2] 1976 P.L.R. 433

**पंजाब राज्य**[3] में उसी स्वर में किए गए टिप्पणियों पर भी निर्भरता की गई। इन आधारों पर तर्क दिया गया कि क्योंकि दूध के नमूने का विश्लेषण करने पर पाया गया कि इसमें दूध की वसा निर्धारित न्यूनतम मानक से अधिक थी और केवल दूध के ठोस पदार्थों में, जो वसा नहीं हैं, 8.5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से कम थे, तो उक्त भिन्नताओं को एक-दूसरे के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है और दूध को अधिनियम के अंतर्गत मिलावटी के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह तथ्य स्वीकार करने योग्य है कि जगत राम के मामले में किए गए टिप्पणियों और हंस राज के मामले में किए गए टिप्पणियों (दो में से एक आधार पर बरी करने के संबंध में) ने याचिकाकर्ता की ओर से लिए गए स्थान को स्पष्ट रूप से समर्थन दिया है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि ये **पंजाब राज्य बनाम तेजा सिंह**[4] मामले में पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित प्राधिकारिक निर्णय के सीधे संघर्ष में हैं। इसमें विचाराधीन विशिष्ट कानूनी मुद्दे निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किए गए थे; –

> (1) क्या लोक विश्लेषक द्वारा प्रकट किए गए दूध के विभिन्न घटकों के प्रतिशत को जोड़ना स्वीकार्य है और उसके बाद दूध की निर्धारित मानकों से समग्र रूप से कमी या अन्यथा के बारे में निष्कर्ष निकालना संभव है?
>
> (2) क्या अदालत लोक विश्लेषक द्वारा दूध के विश्लेषण के दौरान दर्ज की गई निष्कर्षों में थोड़ी या मामूली त्रुटि के मार्जिन को मान लेने का अधिकार रखती है?
>
> (3) क्या अधिनियम द्वारा निर्धारित मानक से नगण्य या मामूली विचलन को अनदेखा किया जा सकता है और उस आधार पर बरी करने का निर्णय दिया जा सकता है?
>
> यह स्पष्ट और कट्टर रूप से निर्धारित किया गया था कि उपरोक्त सभी तीन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक में दिया जाना चाहिए।

4. उपरोक्त के मद्देनजर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि निर्धारित मानक से विचलन के प्रतिशत के जोड़ या घटाव की प्रक्रिया का सहारा लेकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वस्तु मिलावटी नहीं है या निर्धारित मानक से मामूली विचलन को अनदेखा किया जा सकता है। हालांकि, यही बात प्रतीत होती है जो जगत राम के मामले और हंस राज के मामले में की गई थी। निर्णयों की समीक्षा से यह पता चलता है कि वकीलों ने तेजा सिंह के मामले (उपरोक्त) में अधिकारिक घोषणा को अदालत के ध्यान में नहीं लाने में काफी चूक की थी। सम्मानित

---

[3] 1980(2) P.F.A. Cases 396
[4] 1976 P.L.R 433

न्यायाधीशों के प्रति सबसे बड़े सम्मान के साथ उनके द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण पूर्ण पीठ के साथ संघर्ष में है और इसलिए, इसे यहाँ पर निरस्त किया जाता है।

5. मुख्य मुद्दे पर तर्क को खारिज करते हुए, अधिवक्ता ने यह दावा करने के लिए पीछे हटे कि अधिनियम की धारा 11(3) का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है, क्योंकि अभियोजन ने यह स्थापित नहीं किया था कि खाद्य निरीक्षक ने नमूने को लेने के तुरंत बाद अगले कार्य दिवस पर लोक विश्लेषक को भेजा था। अपीलीय अदालत ने स्थापित तथ्यों की ओर संकेत करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ने जब खाद्य निरीक्षक गवाही दे रहा था, तब नमूने के भेजे जाने की सटीक तारीख को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया था। पाया गया कि नमूना 6 तारीख को लेने के बाद रेलवे पार्सल द्वारा भेजा गया था और यह 13 तारीख को लोक विश्लेषक के पास पहुंचा था, जो इसके अगले कार्य दिवस पर भेजे जाने के साथ संगत हो सकता है। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता यह भी दिखा नहीं पाए कि नमूने के भेजने में हुई मामूली देरी से याचिकाकर्ता को किसी प्रकार का पूर्वाग्रह हुआ था। अधिनियम की धारा 11(3) में नियम कानूनी या निर्देशात्मक होना चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा **G. चंद्रमौली और अन्य बनाम राज्य**[5] मामले में की गई है। सिद्धांत और पूर्व निर्णयों का संदर्भ लेते हुए, इस संदर्भ में निष्कर्ष इस प्रकार निकाला गया है: –

> उपरोक्त सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए, अगर हम अधिनियम की योजना के दृष्टिकोण से धारा 11(3) के प्रावधानों का परीक्षण करें, तो यह माना जाना चाहिए कि समय सीमा का पालन व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है और यह सार्वजनिक कर्तव्य के स्वरूप में भी नहीं है तथा किसी भी देरी से सामान्य असुविधा या अन्याय नहीं होता है। इसलिए, यह प्रावधान केवल निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं। दूसरी ओर, इस प्रावधान को अनिवार्य मानने की व्याख्या से विधायिका के मुख्य उद्देश्य को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं मिलता है। हालांकि, यह नहीं समझा जाना चाहिए कि खाद्य निरीक्षक पर लोक विश्लेषक को बिना किसी देरी के नमूना भेजने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसा कि पहले ही उल्लेखित है, यह प्रावधान खाद्य निरीक्षकों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने से रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि नमूने बिना किसी देरी के भेजे जाएं, ताकि वे विश्लेषण के लिए उपयुक्त हो सकें।"

पहले से चर्चित जमीन पर दोबारा न चलने के लिए, यह कहना पर्याप्त होगा कि हम उपरोक्त मामले में दी गई तर्कसंगति और निष्कर्षों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया यह तर्क भी खारिज किया जाना चाहिए।

6. याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने फिर वही तर्क उठाए जो अपीलीय अदालत के विस्तृत निर्णय में कुशलतापूर्वक खारिज किए गए थे। पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में यह कहना पर्याप्त होगा कि हम उनसे सहमत हैं और वही यहाँ पुष्ट किए जाते हैं। आपराधिक संशोधन बिना किसी मेरिट के है और इसे यहाँ खारिज किया जाता है।

---

[5] 1978 Cr. L.J.549

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

निशा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा